'अप्प दीपो भव'

वॉयस ऑफ बुद्धा

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2013-15
WPP Licence No.- U(C)-101/2013-15
R.N.I. No. 68180/98

प्रकाशन तिथि- 31 जुलाई, 2014

मूल्य : पाँच रूपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज (राम राज) चेयरमैन - जस्टिस पब्लिकेशंस, टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, फोन : 23354841-42

Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com

● वर्ष : 17 ● अंक 17 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● 16 से 31 जुलाई, 2014

घृणा घृणा से नहीं प्रेम से खत्म होती है, यह शाश्वत सत्य है।

&xkSre cq)

सामाजिक न्याय मंत्रालय पर डॉ. उदित राज का संसद में भाषण

बजट पास करते समय संसद से विभिन्न मंत्रालयों का अनुदान की मांग की राशि स्वीकृति कराई जाती है। 23 जुलाई को चार मंत्रालयों का बहस कराकर के अनुदान की राशि की स्वीकृति करानी थी। सबसे पहले सड़क परिवहन पर चर्चा होनी थी और अंत में सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय की। शुरू में ही पता लग गया कि जब तक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की बारी आएगी तब तक शून्यकाल आ जाएगा। डॉ. उदित राज स्पीकर महोदया से मिले और कहा कि इस मंत्रालय का संबंध 25 प्रतिशत दलित-आदिवासी से गहरा तो है ही, पिछड़े वर्ग का कल्याण की तमाम योजनाएं भी इसमें है। इतनी बड़ी आबादी से संबंधित मंत्रालय पर चर्चा न हो और अनुदान की राशि स्वीकृति हो जाए तो इससे बड़ी और क्या विडंबना होगी? डॉ. उदित राज संसदीय कार्यमंत्री श्री वेंकैया नायडू को इस सच्चाई से अवगत कराया। इस विभाग के मंत्री श्री थावरचंद गहलोत और सचेतक श्री अर्जुनराम मेघवाल को अवगत कराया गया और इनका सहयोग मिला। इतिहास में पहली बार इस मंत्रालय के ऊपर बहस हुई और कुछ मौलिक सवाल उठाए गए जो पूर्व में नहीं किया जा सका।

DR. UDIT RAJ (NORTH WEST DELHI): Hon. Chairperson, our hon. Finance Minister has just presented the Budget. The allocation made by him in the Budget for SCs in the Scheduled Castes Plan Budget is Rs.50,548 crore and for Scheduled Tribes the allocation is Rs.32,387 crore. This works out to be 8.79 percent whereas it should be around 16 per cent. मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि यह लगभग 16 प्रतिशत होना चाहिए और अनुसूचित जनजाति के बारे में 7.5 प्रतिशत होना चाहिए। मैं इस पर बाद में आऊंगा लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता की बात है, हो सकता है कि अधिकारियों की वजह से गड़बड़ी हुई है, वह यह है कि अगर आप पृष्ठ संख्या 316 देखें तो इसमें जो 50 हजार करोड़ रूपये हैं which is going to be spent for SCs and STs, now it seems that it is not going to be spent by the Central Government. It is going to be spent by the States and UTs. मैं दो-तीन फिगर्स आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो 2012-13 में 1654 करोड़ हुआ करती थी, वह सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के हेड के अंदर होती थी। यही राशि इस बार जो स्टेट एंड यूटी प्लान में चला गया है 1499 करोड़। यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह पैसा स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया जाएगा, गवर्नमेंट इसको खर्च करेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करेगी। अगर थ्रू स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करें तो पहले से ऐसा चला आ रहा है। लेकिन पहले भी अटैम्प्ट किया गया था कि यह मनी स्टेट को ट्रांसफर किया जाना चाहिए। मंत्री महोदय से मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह पैसा स्टेट को दिया जा रहा है? we do not have faith in many of the State Governments. ये तमाम जो राज्य सरकारें हैं, फ्यूडल हैं, एंटी दलित भी हैं। उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं कि एंटी रिजर्वेशन का काम सोशल और पॉलिटिकल आर्गेनाइजेशन करते हैं लेकिन वहां की सरकार ने किया है। How can we have faith in them? उनमें हमारा कोई विश्वास नहीं है। इसलिए यह पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट के थ्रू ही जाना चाहिए।

Similarly, there is a machinery for implementation of protection of Civil Rights, 1955 यह पहले 97 करोड़ था। हालांकि कुछ जगह राशि कम भी किये हैं। जैसे गर्ल्स होस्टल्स में पहले के बजट के हिसाब की तुलना में इस बार कम हुआ है। उसी प्रकार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में भी राशि कम हुआ है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर बहुत ज्यादा न बढ़ाएं तो देखें पिछले वर्ष की तुलना में महंगाई भी बढ़ी है। इसको एनहैन्स करने की कोशिश करिये। इसी तरह से ओबीसी के साथ भी हुआ है। ओबीसी का भी जो बजट है, पहले मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट के थ्रू इंप्लीमेंट होता था। यही पैटर्न उसमें भी दिखाया गया है। It is likely that the officers have misled. Of course, we know that the buereacracy does. I was part of the bureaucracy.

(r3/1725/mm/kmr)

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यह पहले जैसा होना चाहिए न कि यह पैसा राज्यों को दिया जाना चाहिए। मैं एक बात ओबीसी कमीशन के बारे में कहना चाहूंगा। OBC Commission is toothless. OBC Commission has to be

शेष पृष्ठ 5 पर ...

सिविल सर्विसेज में आकर्षण क्यों?

डॉ. उदित राज

इस वर्ष के सिविल सर्विसेज में सफल होने वाले अंग्रेजी माध्यम वाले परीक्षार्थी बहुतायत में थे। इस पर मुखर्जी नगर, दिल्ली से विरोध का सुर निकला और अन्यत्र जगहों पर भी असर किया। 2009 में हिन्दीभाषी सफल उम्मीदवार 25.4 प्रतिशत थे, 2010 में 13.9, 2011 में 9.8 और 2013 में 2.3 प्रतिशत ही रह गए। 2013 में कुल सफल उम्मीदवार 1122 थे जिसमें हिन्दीभाषी 26 ही पास कर पाये। यह सबसे बड़ा आक्रोश का कारण है जिससे प्रतिस्पर्धा में बैठने वाले छात्र एवं नौजवान सड़क पर उतरे हैं।

मैंने स्वयं 1988 की सिविल सर्विसेज का परीक्षा दी थी और भारतीय राजस्व सेवा में चुना गया। 1990 में प्रथम तैनाती सहायक आयकर आयुक्त के पद पर हुयी। मैं आर्थिक परिस्थितियांवश इस सेवा में गया और 2003 में अतिरिक्त आयकर आयुक्त पद पर से इस्तीफा दे दिया। अपवाद को छोड़कर के इस सेवा में प्रवेश करने के लिए परीक्षार्थियों के लिए इससे बड़ा कोई भारत में अवसर नहीं दिखता। 1980 के पहले विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के परीक्षार्थी बहुत कम सिविल सर्विसेज के लिए प्रयास करते थे। यह भी कारण था कि उस समय तक नौकरशाहों की बादशाहत के प्रति आकर्षण हो गया था। आईआईटी के कैंपस पर 80 के बाद इसका प्रभाव साफ दिखने लगा था। पहले दो वैकल्पिक विषय और सामान्य ज्ञान का पेपर हुआ करते थे। जिसका प्राप्तांक 1800 हुआ करता था और साक्षात्कार का 250 अंक था। वर्तमान में दो सामान्य ज्ञान के पेपर जो 500-500 अंक के हैं, एक वैकल्पिक विषय 500 का है, निबंध 250 और साक्षात्कार 275 का है। इन दोनों व्यवस्थाओं से इंजीनियर्स और डॉक्टर फायदे में रहे और वर्तमान वाले में तो इनका आधिपत्य ही स्थापित हो गया। 1980 से पहले की व्यवस्था विज्ञान के परीक्षार्थियों के पक्ष में इतनी नहीं थी।

आजादी के बाद केरल के लोग ज्यादा सफल हुआ करते थे और धीरे-धीरे इलाहाबाद सिविल सेवा सर्विसेज का केंद्र बना इसके बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय। 1980 के बाद इंजीनियरों और डॉक्टरों में इसका आकर्षण पैदा हुआ। भूमंडलीकरण के कारण बीच में लगा कि निजी क्षेत्र में देश-विदेश में सिविल सर्विसेज से ज्यादा पैसा और सुविधाएं पाने के अवसर पैदा हो रहे हैं और इसलिए उत्कृष्ट टैलेंट वहां जाने लगेगा। कुछ समय के लिए ऐसा हुआ भी लेकिन सिविल सर्विसेज में जाने का आकर्षण कम नहीं हुआ। उन राज्यों में ज्यादा आकर्षण है जहां पर विकास रूक गया है। हर समाज में कुछ लोग ऐसे होते ही हैं जिन्हें शिखर पर पहुंचने की प्रवृत्ति होती है। जब व्यवसाय, कला और अन्य क्षेत्रों में बेहतर करने का अवसर ही न मिले तो ऐसे में सिविल सर्विसेज एक ही विकल्प दिखता है। बिहार में उद्योग-धंधे कम हैं और अन्य अवसर भी खास नहीं है जिससे कि वहां के लोगों की महत्वकाक्षाएं पूरी हो सके। सन् 1980 के दशक से सिविल सर्विसेज के प्रति ज्यादा ही बिहार के लोगों में आकर्षण पैदा हुआ और अब कहा जाने लगा है कि आने वाले कुछ साल में देश का कोई ऐसा जनपद नहीं होगा जहां बिहार के अधिकारियों का उच्च पद में भागीदारी न हो। आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक आदि प्रदेशों में कारपोरेट संस्कृति, आईटी और अन्य अवसर उत्पन्न हो गए इसलिए वहां के नौजवानों में मात्र सिविल सर्विसेज ही एक विकल्प नहीं है और यही कारण है कि शुरुआत में उन्होंने बढ़त ली थी लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया है।

यह भी जांचना आवश्यक है कि सिविल सर्विसेज में जाने की इतनी होड़ क्यों है? यह देखा गया है कि

शेष पृष्ठ 3 पर ...

'नसोसवायएफ' का चार दिवसीय कैडर कैंप दिल्ली में संपन्न

डी. हर्षवर्धन दवणे

नेशनल एससी, एसटी, ओबीसी स्टूडेंट एंड यूथ फ्रंट (नसोसवायएफ) का चार दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर 17 जुलाई से 20 जुलाई तक अंबेडकर भवन, नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस चार दिवसीय राष्ट्रीय कैडर कैंप में देश के विभिन्न राज्य के सैकड़ों युवा और छात्र नेता उपस्थित थे। शिविर के पहले दिन छात्र एवं युवा नेताओं को ''नसोसवायएफ की जरूरत क्यों?'' विषय पर नेशनल कोऑर्डिनेटर डी. हर्षवर्धन ने संबोधित करते हुए कहा कि देश में दलित, आदिवासी, ओबीसी का राष्ट्रीय स्तर का एक भी संगठन स्थापित नहीं हुआ था। ऐसा करने का किसी ने प्रयास भी नहीं किया। इसकी कमी पूरी करने एवं निजी क्षेत्र में आरक्षण दिलाने, जातिविहीन समतामूलक समाज की स्थापना के लिए 'नसोसवायएफ' का निर्माण डॉ. उदित राज के नेतृत्व में किया गया।

पहले दिन के तीसरे सत्र में 'बाबा साहेब अंबेडकर और उनका राष्ट्र निर्माण का कार्य' विषय पर बैंगलुरु (कर्नाटक) के प्रसिद्ध वक्ता अरविंद बौद्धा ने मार्गदर्शन करते हुए कहा कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर देश के एकमात्र राष्ट्रवादी एवं परम देशभक्त नेता थे जो हर पल अपने देश के बारे में चिंता करते थे। 'थॉट्स ऑन पाकिस्तान', पार्टिशन ऑफ इंडिया जैसी किताबें बाबा साहेब की राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत थी। इतना ही नहीं जब धर्मान्तरण का मुद्दा आया तो ईसाई, मुस्लिम धर्म को न अपनाते हुए भारत के संस्कृति का एक रूप बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। इससे उनकी राष्ट्रभक्ति समझ में आती है। जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली तो उन्होंने राष्ट्र को मजबूत करने एवं देश के स्त्री एवं पुरुष को एक समान स्तर पर लाने के लिए 'हिंदू कोड बिल' का निर्माण करके देश में फैली स्त्री-पुरुष असमानता को मिटाने का प्रयास किया। आजादी के पहले भी उन्होंने देश के बंटवारे का विरोध किया था। यह उनके राष्ट्रभक्त होने का प्रमाण है।

इस कैंप के दूसरे दिन 'नसोसवायएफ' की विचारधारा एवं उद्देश्य' विषय पर डी. हर्षवर्धन ने कहा कि 'नसोसवायएफ' की विचारधारा अंबेडकरवादी है। 'नसोसवायएफ' एक अंबेडकरवादी छात्र एवं युवाओं का संगठन है। जातिविहीन समतामूलक समाज की स्थापना करना, समान एवं अनिवार्य शिक्षा, सामाजिक न्याय और समान अवसर का कार्य करना ही 'नसोसवायएफ' का उद्देश्य है।

शिविर के तीसरे दिन 'जातिविहीन समतामूलक समाज और राज्य समाजवाद की स्थापना' विषय पर 'नसोसवायएफ' के संरक्षक एवं सांसद डॉ. उदित राज ने कहा कि अंबेडकरवाद से ही देश में जातिविहीन समतामूलक समाज की स्थापना होगी। अंबेडकरवादी आंदोलन ही देश में समानता स्थापित कर सकता है।

देशभर से आए युवा एवं छात्र नेताओं के साथ डॉ. उदित राज (बीच में)

डॉ. उदित राज ने आगे कहा कि निजी क्षेत्र में आरक्षण हमारे जीवन-मरण का प्रश्न है। त्याग, समर्पण के बिना हम अपने अधिकार नहीं पा सकते। हमारे युवाओं में अपने अधिकारों को पाने के लिए मर-मिटने का जज्बा होना चाहिए। अगर अपने अधिकार मांगने से न मिले तो उसे छीन लेना होगा। हमें बाबा साहेब के आंदोलन को जिंदा रखने के लिए युवाओं को अभी से तैयार करना होगा। इन युवाओं को अंबेडकर आंदोलन से जोड़ना होगा और ये काम नेशनल एससी, एसटी, ओबीसी स्टूडेंट एंड यूथ फ्रंट कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। 'नसोसवायएफ' का निर्माण ही अंबेडकरवादी आंदोलन को बचाने व निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए किया गया है।

तीसरे दिन के दूसरे सत्र में 'निजी क्षेत्र में आरक्षण' विषय पर डी. हर्षवर्धन ने कहा कि निजीकरण के माध्यम से सरकारी क्षेत्र में नौकरियों को खत्म किया जा रहा है और भूमंडलीकरण, निजीकरण एवं उदारीकरण से नई गुलामी का आगाज हुआ है। इसलिए दलित, आदिवासी, ओबीसी के लिए निजी क्षेत्र में आरक्षण की हम मांग करते हैं।

इस चार दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में 'नसोसवायएफ' के देश के विभिन्न राज्यों के छात्र एवं युवा नेता उपस्थित थे। इस कैडर कैंप में रवि प्रकाश, नागेश सोनुले, गौतम गायकवाड़ (महाराष्ट्र), राज बोड़ात, भंवर बहादुर, अशोक कुमार (राजस्थान), प्रताप सिंह अहिरवार, मुकेश योगी, सतेंद्र सहगर, हेमंत उपाध्याय (मध्यप्रदेश), धर्मेंद्र कुमार, श्रवण कुमार राज (उत्तर प्रदेश), अमृत बोड़ात (गुजरात), रंजित हलदर, सुदेव विश्वास (पश्चिम बंगाल), अजय पासवान (बिहार), विरेंद्र कुमार, रवि कुमार (हरियाणा) एवं अन्य प्रमुख नेतागण उपस्थित थे।

डा0 उदित राज ने संसद में बजट पर अपना पक्ष रखा

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2014 : भारतीय जनता पार्टी की ओर से डा0 उदित राज ने आज संसद में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यह पहला ऐसा बजट है जो बहुत संतुलित है। किसी विशेष वर्ग या क्षेत्र के पक्ष में कोई झुकाव नहीं है, बल्कि सभी को संबोधित करता है, चाहे वे गरीब हों या अमीर अथवा व्यापारी, निवेशक, किसान, विदेशी व्यवसायी। वित्त मंत्री, श्री अरूण जेटली ने अच्छे दिन लाने का बजट पेश किया है। वित्तीय घाटे को 4.1 रखने का लक्ष्य निर्धारित किया है और वर्ष 15 और 16 में क्रमशः 3.6 और 3 प्रतिशत। डा0 उदित राज ने कहा कि वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए कर का दायरा बढ़ाना चाहिए। चाहे भले ही खर्च में कटौती क्यों न करना पड़े। वित्तीय घाटा कम होने से न केवल देशी और विदेशी व्यापारियों को बढ़ावा मिलेगा बल्कि निवेश भी बढ़ेगा। सरकार को चाहिए कि बैंकों के लोन की वापसी के लिए प्रयास करे। वित्तमंत्री ने कृषि, बचत, स्किल, इन्फ्रास्ट्रक्चर और सुशासन के माध्यम से विकास दर 7-8 पर बनाए रखने का लक्ष्य रखा है। बैंकों को पहली बार यह सहूलियत मिली कि वे एसएलआर और सीआरआर शर्तों को शिथिल करते हुए पैसे का इंतजाम करके इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में लंबी अवधि के लिए बांड इत्यादि जारी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान है। किसानों के लिए नेशनल मार्केट बनाया जाएगा ताकि अपने उत्पाद को बिना रोक-टोक बेच सकें। नाबार्ड को 2000 करोड़ रुपये देकर 2000 उत्पादनकर्त्ताओं का संगठन बनाने के लिए प्रोत्साहन किया गया है। 5000 करोड़ रुपये वेयरहाउसिंग के निर्माण के लिए रखा गया है। इससे किसानों को काफी लाभ मिलेगा।

डा0 उदित राज ने आगे कहा कि कर के क्षेत्र में कई सराहनीय सुधार कार्य किए गए हैं। सी.बी.डी.टी. एवं सी.बी.ई.सी. द्वारा एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा जो करदाताओं को समय-समय पर विभिन्न मुद्दों पर सलाह देने का कार्य करेगा। अभी तक एडवांस रूलिंग की सुविधा प्रवासी भारतीयों को ही मिलती थी लेकिन अब भारतीय व्यापारियों को भी यह सुविधा मिलेगी। सेटलमेंट कमीशन का दायरा बढ़ाने पर जोर दिया गया है, ताकि कर संबंधित मुकदमें जल्दी निबटाए जा सकें। इस समय 4 लाख करोड़ रुपये का टैक्स कानूनी पेंच में फंसा पड़ा है, जिसका निबटान करने के लिए सार्थक कदम उठाए जाएंगें। विदेशी निवेशक अभी तक इसलिए भी डरते थे कि बीते हुए वर्ष की तिथि से कानून बना दिए जाते थे लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।

डा0 उदित राज ने वित्तमंत्री एवं प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया कि दिल्ली में पानी की कमी को दूर करने के लिए 500 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा है। उन्होंने कहा कि पहले की सरकार द्वारा आर्थिक जगत् में गड़बड़ियों को सुधारने की एक बहुत बड़ी चुनौती सरकार के सामने है। रेलवे भाड़ा बढ़ाने का प्रस्ताव यू.पी.ए. सरकार का ही था। 50 हजार करोड़ रुपये का इक्कम टैक्स रिफंड 31 मार्च, 2014 के बाद दिया गया जिससे सरकार की इस वर्ष की आय में फर्क पड़ा। राज्यों को 32 हजार करोड़ रुपया सरकार की देनदारी है, वह भी एक चुनौती है लेकिन बजट को देखते हुए लगता है कि न केवल इन चुनौतियों का सरकार सामना करेगी बल्कि अच्छे दिन भी स्थापित करेगी।

मोदी सरकार की ऐतिहासिक पहल

23 जुलाई, 2014, नई दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी से सांसद डॉ. उदित राज ने कहा कि यह पहली बार हुआ जब लोकसभा में बजट पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय पर चर्चा हुई। संसदीय मंत्री श्री वेंकैया नायडू एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत को उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। कांग्रेस लगभग 55 साल केंद्र की सरकार में रही और उसके समय में यह कभी न हो सका। अनुसूचित जाति की आबादी के अनुसार योजनागत बजट का पैसा आवंटित होना चाहिए और कांग्रेस सरकार ने कभी ऐसा किया नहीं और इस बार के बजट में कुछ बढ़ोतरी हुई है। इसके लिए वित्तमंत्री अरूण जेटली को धन्यवाद देना चाहिए।

डॉ. उदित राज ने संसद में कहा कि केंद्र सरकार जो धनराशि दलितों एवं आदिवासियों के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के द्वारा इनका उत्थान कर रही है, यह देखा जाए कि राज्य सरकारें इसका दुरूपयोग न कर पाये। पूर्व में देखा गया है कि इनके पैसे का दुरूपयोग किया गया है। एशियाड खेल में अनुसूचित जाति के स्पेशल कंपोनेंट की 700 करोड़ से अधिक धनराशि खर्च कर दी गयी थी। उन्होंने संसद में कहा कि यह अकसर होता है कि अनुसूचित जाति स्पेशल कंपानेंट प्लान और अनुसूचित जनजाति प्लान का पैसा अन्य विभिन्न योजनाओं में लगा दिया जाता है और तर्क यह दिया जाता है कि इस्तेमाल तो ये भी करते हैं। मान लिया कि सड़क का निर्माण कर दिया गया तो तर्क यह दिया जाता है कि इसका प्रयोग अनुसूचित जाति/जनजाति के लोग भी करते हैं और ऐसे में इस योजना का मतलब क्या है? उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के माध्यम से योजनाओं को क्रियांवित करती है लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि यहां से राशि राज्य को सीधे भेज दिया जाए। उत्तर प्रदेश में तो बहुत संभावनाएं है कि दलितों का पैसा दुरूपयोग कर दिया जाए क्योंकि वहां की सरकार ही खुलकर के दलित विरोधी कार्य करती है।

डॉ. उदित राज ने कांग्रेस की आज संसद में खूब खबर ली और कहा कि वे कम से कम भाजपा पर आरोप नहीं लगा सकती क्योंकि यदि आरक्षण न हुआ होता तो आज भी दलित-आदिवासी संसद में प्रवेश नहीं कर सकते थे। इसके लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। अगर उसकी नियत सही होती तो कुछ दलित-आदिवासी इतना उत्थान कर चुके होते कि बिना आरक्षण के ही संसद-विधानसभा में वे चुनकर आ जाते। कांग्रेस के समय में कभी भी योजनागत बजट का 8 प्रतिशत से अधिक राशि आवंटित नहीं हुई जबकि आबादी के हिसाब से 16.6 प्रतिशत होना चाहिए। पूर्व की कमियों को कुछ दिनों में सरकार सुधार नहीं सकती और इसके लिए समय लगेगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इनके लिए अब तक जो न किया जा सका है वह उनके ही कर-कमलों से होना है।

अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ
All India Confederation of SC/ST Organisations

Dr. Udit Raj
National Chairman

Corres.: T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001
Tel: 011-23354841, 011-23354842, Fax: 011-23354843
Email: dr.uditraj@gmail.com, web.: www.uditraj.com

परिपत्र संख्या : 80 दिनांक : 26/07/2014

प्रिय

जिन परिस्थितियों में मैंने संसद पहुंचने का फैसला लिया, अधिकतर परिसंघ के लोग जानते और समझते हैं। मैं उत्तर पश्चिम दिल्ली से चुनकर लोकसभा में पहुंचा हूं। इसमें मेरी व्यक्तिगत इच्छा या संतुष्टि बाद में है और मुख्य उद्देश्य दलित, आदिवासी और वंचित समाज की भागीदारी पहले। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के समय भी यही प्रतिबद्धता मैंने दुहराई थी और यह पूरा जीवन रहेगा। संसद में पहुंचने का मतलब तभी साकार होगा जब परिसंघ के लोग काम को और तेज करेंगे। अकेले भारतीय जनता पार्टी को 282 सीटें मिली हैं जबकि मुद्दा आरक्षण या दलित उत्थान आदि चुनाव में नहीं बन पाया था। किसी भी पार्टी का मुद्दा चुनाव में आरक्षण या दलित सशक्तिकरण नहीं था। जब आरक्षण और दलित अधिकार की बात उठे बिना सत्ता में पहुंचा जा सकता है तो मैं कितना पार्टी और संसद में कर सकूंगा जब तक कि सामाजिक आंदोलन तेज न हो। इस बार मेरे आंदोलन के साथियों ने भाजपा को चुनाव में पूरा समर्थन किया है और उसका पुरस्कार मिलना चाहिए ऐसा मैं समझता हूं। भाजपा में शामिल होने से पहले मेरी प्रमुख शर्त यही थी कि दलित समाज को भागीदारी हर क्षेत्र में मिले, वह भाजपा का पूरा साथ देगा और एक बार नहीं बल्कि लगातार।

परिसंघ अकेले गत् 17 साल से आरक्षण बचाने की लड़ाई लड़ रहा है लेकिन अपेक्षित समर्थन नहीं मिला। केवल ब्राह्मणवाद की आलोचना करना आंदोलन समझ लिया जा रहा है जबकि यह गलत है। हमें सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना है और जिनके हाथ में देश की धन-संपत्ति और सत्ता है उसका साथ देकर विभिन्न क्षेत्र में भागीदारी लेना है। नई आर्थिक नीति की वजह से आरक्षण घटा है। सामाजिक आंदोलन यदि तेज होता है तो हम विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी के लिए स्वयं सक्षम हो जाएंगे।

मेरे संसद में पहुंचने का असर दिखने लगा है। अब के पहले कभी भी किसी बजट सत्र के समय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता पर चर्चा और वोटिंग शायद ही हुई हो। पर्यावरण हो या अन्य छोटे-छोटे मंत्रालय पर बहस होना स्वाभाविक है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय पर बहस का मामला संसद के कामकाज के सबसे अंत में रखा गया था। इसलिए जब तक उसका समय आता संसद उठ गयी होती। मैं स्पीकर - श्रीमती सुमित्रा महाजन, संसदीय कार्य मंत्री - श्री वेंकया नायडू, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री - श्री थावर चंद गहलोत और मुख्य सचेतक - श्री अर्जुन मेघवाल से मिला और कहा कि 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जन जाति की आबादी ही नहीं बल्कि पिछड़े वर्ग से संबंधित मंत्रालय पर अगर बहस नहीं होती है तो समाज क्या सोचेगा? और मैं क्या जवाब दूंगा? आपको अपार हर्ष होना चाहिए कि पहली बार इस पर चर्चा हुई और पार्टी की ओर से मैं पहला वक्ता था। आज़ादी के बाद से अभी तक हमारे साथ क्या-क्या अन्याय किया जाता रहा, उस पर पहली बार संसद में चर्चा हुई।

अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए परिसंघ को फिर से नई गति देने का समय आ गया है और इसलिए इस बार का राष्ट्रीय अधिवेशन 16-17 अगस्त, 2014 को प्रातः 10 बजे से स्पीकर हॉल, कांस्टीट्यूशन क्लब, भारतीय रिजर्व बैंक के पीछे (नजदीक पटेल चौक मैट्रो स्टेशन) नई दिल्ली में रखा गया है। यह कार्यक्रम परिसंघ के राष्ट्रीय महासचिव श्री विनोद कुमार, राष्ट्रीय महामंत्री श्री नेतराम ठगेला एवं प्रदेश अध्यक्ष डॉ. नाहर सिंह के संरक्षण में हो रहा है, आने की अग्रिम सूचना उन्हें अवश्य दें, उनसे संपर्क करने के लिए मोबाइल नंबर :- 09871237186, ईमेल : vinodkumarijp@gmail.com, है।

सद्भावनाओं सहित,

आपका,
उदितराज
(उदित राज)

शेष पृष्ठ 1 का ...

सिविल सर्विसेज में आकर्षण क्यों?

जहां पर सामंती और पारंपरिक सोच के लोग हों वहां के लोग ज्यादा आकर्षित होते हैं। उसका कारण यह है कि सिविल सर्विसेज में न केवल अच्छा वेतन है बल्कि पावर भी है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे प्रदेशों के गांवों में पुलिस के थानेदार की इज्जत एक प्रोफेसर से ज्यादा होती है। इन परीक्षार्थियों को यह विकल्प दिया जाए कि इससे दो या तीन गुना ज्यादा वेतन एवं सुविधा निजी क्षेत्र में मिलेगा तो भी वहां नहीं जाना चाहेंगे। साक्षात्कार के समय सभी को यह तैयार कराया जाता है कि जब बोर्ड में पूछा जाए कि इसी सेवा में क्यों जाना चाहते हो तो एक रटा-रटाया उत्तर होता है कि प्रशासन में जाकर के समाज और देश की सेवा करने का इच्छा है। यह अधूरा सच है और इसका उजागर करना एक नैतिक और विवादित प्रश्न खड़ा कर देगा इसलिए इतना ही इशारा समझदार के लिए काफी है।

भारतीय भाषाओं के छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी मांग जायज है लेकिन समग्र परिस्थिति के विश्लेषण का अभाव है। इनका कहना है कि हिंदी में किया हुआ अनुवाद असफलता का एक कारण है। इसके अलावा सीसैट भारतीय भाषाओं के परीक्षार्थियों को रोकने का कार्य कर रहा है। यह परीक्षा प्रणाली अंग्रेजीभाषी परीक्षार्थियों के पक्ष में ज्यादा है। इनके असंतोष में वह बात देखने को नहीं मिली जो मूल कारण हैं। 1990 के बाद निजीकरण का दौर बढ़ा और शिक्षा जगत इससे न बच सका। आज लगभग 60 प्रतिशत उच्च शिक्षा निजी क्षेत्र के दायरे में पहुंच गयी है और प्राथमिक शिक्षा की बात ही क्या कहना जो व्यवसायिक और लाभकारी शिक्षा है। उसका एक बड़ा हिस्सा निजी क्षेत्र में जा चुका है। निजी क्षेत्र के शिक्षा संस्थानों में न केवल अच्छे शिक्षक होते हैं बल्कि सुख-सुविधाएं सरकारी स्कूलों से कई गुना ज्यादा होती है। इसके अतिरिक्त ट्यूशन भी कराया जाता है और घर में मां-बाप भी कदम-कदम पर निगरानी रखते हैं। ज्यादातर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नाममात्र की होती है और ये जो तीनों सुविधाएं हैं वे वंचित रहते हैं। यह भी एक यथार्थ है कि ज्यादातर पढ़ाकू छात्र शुरू से गणित और विज्ञान की ओर मुखातिब हो जाते हैं और इनका पढ़ाई का माध्यम शुरुआत में अंग्रेजी न भी हो लेकिन बाद में हो जाता है। यह भी एक कारण है कि भारतीय भाषाओं के छात्र असफल हो रहे हैं। जो नई शिक्षा प्रणाली आई है जिसके तहत बच्चे को दसवीं तक परीक्षा न देना हो उससे भारतीय भाषाओं के परीक्षार्थियों का सबसे ज्यादा हानि हो रही है। इस व्यवस्था को फौरन समाप्त करना चाहिए। शिक्षा का निजीकरण और परीक्षा से मुक्ति के कारण भारतीय भाषाओं के उम्मीदवारों का ज्यादा हानि हो रही है। सीसैट, अनुचित अनुवाद और अंग्रेजी भाषा तो कारण है ही।

इस समय देश के समक्ष यह चुनौती है कि इस संकट से कैसे निपटा जाए। अगर अंग्रेजी हटाते हैं तो भी मुश्किल है। भारत सरकार का ज्यादातर काम अंग्रेजी में ही होता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में तो अंग्रेजी के बगैर गुजारा नहीं है। दक्षिण भारतीय सिविल सर्वेंट अगर उत्तर भारत में आता है और उत्तर भारत वाला दक्षिण भारत में जाता है तो बिना अंग्रेजी के कैसे संवाद स्थापित कर सकेगा? सीसैट में डिसिजन मेकिंग, न्यूमेरिकल स्किल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आदि की वजहों से भारतीय भाषा के छात्र अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। यदि इन्हें हटा दिया जाता है तो जिस टैलेंट की सिविल सर्विसेज में चाहत है, उससे हम वंचित रह जाते हैं। एक नौकरशाह में औसत ज्ञान, गणित, निर्णय लेने और विश्लेषण करने की क्षमता होना चाहिए। वर्तमान में यही असली चुनौती है कि कैसे संतुलन बनाया जाए ताकि जिस प्रतिभा की आवश्यकता है वह बनी रहे और हिंदीभाषी परीक्षार्थी नुकसान में न रहे।

अपराध का सिलसिला

सय्यद मुबीन जेहरा

बैंगलुरु के एक नामी स्कूल में छह वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार और उसके बाद स्कूल प्रशासन की खामोशी इस बात का सबूत है कि हमारे समाज में किस प्रकार के वहशी और दरिंदे घूम रहे हैं। अगर एक मासूम बच्ची तक सुरक्षित न हो और स्कूल प्रशासन अपना पल्ला झाड़ने में लग जाए तो इससे यह साबित होता है कि हमारा समाज महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किसी भी स्तर पर गंभीर नहीं है। बंगलुरु की इस घटना पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय को संज्ञान लेकर स्कूलों को दिशा-निर्देश जारी करना चाहिए।

पूरे देश में हर दिन औसतन 92 महिलाएं बलात्कार का शिकार होती हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के 2013 की रपट के अनुसार यों तो हर तरह के अपराध बढ़े हैं, लेकिन चिंता की बात है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध घटने का नाम नहीं ले रहे हैं। अफसोस की बात है कि इन अपराधों को भी मीडिया में दिखाते समय राजनीति को सामने रखा जाता है। किसी एक राज्य या एक पार्टी को निशाने पर ले लिया जाता है या फिर एक वर्ग को। इसके अलावा दंगों में या भीड़ द्वारा महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की रिपोर्ट दिखाने या उनकी निंदा करने में भी दोहरा मापदंड अपनाया जाता है। ऐसे में चिंता का विषय है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर कैसे रोक लगे।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार मध्यप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और असम बलात्कार की सबसे अधिक घटनाओं वाले पहले पांच राज्यों में शामिल हैं। मगर मीडिया की कवरेज देखें तो ऐसा लगता है जैसे कुछ एक ही राज्यों में ऐसे अपराध हो रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध में राजनीति न सिर्फ समाज की संवेदनहीनता को दर्शाती, बल्कि अपराध के विरुद्ध जंग को भी कमजोर करती है। देश में जिस गति से अपराध बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से पुलिसकर्मियों की संख्या नहीं बढ़ रही है। पुलिस सुधार की बात तो बहुत होती है, पर इस दिशा में कोई पहल नहीं हो सकी है। अदालतें भी कम पड़ रही हैं, उनमें अनगिनत मामले लंबित हैं। इन परिस्थितियों में अपराध को कम कर पाना चुनौती है। हालांकि इसके बावजूद कुछ आशा के संकेत भी मिले हैं।

एक तो यह कि पुलिस की कार्यक्षमता में कुछ वृद्धि हुई है। 2012 में जहां पुलिस ने साढ़े चौंसठ प्रतिशत मामले निपटाए थे वहीं 2013 में साढ़े अड़सठ प्रतिशत मामले निपटाए गए। मगर हैरानी की बात है कि दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में बलात्कार की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है।

देश के जिन राज्यों में इन घटनाओं में कमी आई है वह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में बलात्कार के कुछ मामलों में जरूर हंगामा हुआ, पर 2012 में हुई दो हजार छियालीस घटनाओं के मुकाबले 2013 में यह संख्या घट कर एक हजार छह सौ पचासी रह गई। मगर चिंतित करने वाली बात है कि इन घटनाओं में महज चार सौ बाईस मामलों में वारदात करने वाले जान-पहचान वाले थे। यानी ज्यादातर वारदातें बाहरी लोगों द्वारा अंजाम दी गईं। यह समाज में घुल रही आपराधिक प्रवृत्ति को उजागर करती है।

दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में अपराधों की संख्या दोगुनी हो गई है। वहां 2012 में बलात्कार के एक हजार नौ सौ तिरसठ मामले दर्ज हुए, जो 2013 में बढ़ कर तीन हजार पचास हो गए। यहां यह बात भी ध्यान रखनी होगी कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सरकार के दौरान दंगों का एक सिलसिला-सा नजर आता है। मुजफ्फरनगर दंगों और वहां हुए महिलाओं के खिलाफ अपराध की वजह से समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा था। इसके बाद भी वहां से लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराधों की खबरें मिलती रही हैं। इन वारदातों की गूंज विदेशों में भी पहुंची है। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस पर चिंता जताई है।

राजस्थान में भी पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश से अधिक बलात्कार की घटनाएं हुईं- तीन हजार दो सौ पचासी। मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश से अधिक बलात्कार की घटनाएं हुई हैं। मध्यप्रदेश में 2013 में देश में सबसे अधिक बलात्कार की घटनाएं हुईं- चार हजार तीन सौ पैंतीस। महाराष्ट्र में यह संख्या तीन हजार छह सौ तीन है। ये आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध का किसी राजनीतिक दल से कुछ लेना-देना नहीं है, बल्कि समाज का सोच ही इसके पीछे असली दोषी है। इसके बाद पुलिस और कानून आते हैं, जो महिलाओं का विश्वास जीत पाने में विफल रहे हैं। शायद हमारे समाज के ताने-बाने में ही महिला असुरक्षा का बोध है।

जाहिर है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध हर राज्य में हो रहे हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस पार्टी की सरकार है। मगर मीडिया में राजनेताओं के बयानों से ऐसा लगता है जैसे उन्हें केवल विरोधी पार्टी द्वारा शासित राज्य नजर आते हैं। जिनके खिलाफ यह बात की जाती है वे अपने विरोधियों के राज्य के रिकार्ड निकाल कर सामने रख देते हैं। इस तरह एक-दूसरे पर निशाना साधते हुए ये लोग वास्तविक समस्या को भटका देते हैं।

दरअसल, यह सारा मामला हमारे समाज से जुड़ा है। हमारे समाज में महिलाओं को लेकर गलत सोच को बढ़ावा मिला है। पुरुष करे तो ठीक, पर महिला करे तो गलत जैसा सोच समाज को गलत दिशा में ले जा रहा है। मैं महिलाओं के मुंह नहीं लगता, महिला हो इसलिए माफ कर दिया, चूड़ी पहन के बैठ जा, महिलाओं की तरह रोने लगा, औरत हो तो औरत की तरह रहो ज्यादा हवा में मत उड़ो, तुम लड़की हो इसलिए नहीं पढ़ सकती, अरे लड़की बड़ी हो गई है इसके हाथ पीले कर दो, दो लड़कियां सिर पर बोझ बन कर बैठी हैं जैसी महिला विरोधी बातें हमारे समाज की ही देन हैं। ये धारणाएं बताती हैं कि हमारा समाज महिलाओं को लेकर किस तरह के सोच में जीता है।

इस मामले में धर्म, समाज, राजनीति सबको आगे आकर महिलाओं की इज्जत-आबरू की रक्षा करनी होगी। घर से निकलते ही हर मोड़, हर गली में कोई न कोई धार्मिक स्थल नजर आ जाता है, पर क्या हमारे जीवन में धर्म कुछ ऐसा कर पाया है कि हम अपराध से बचें। धर्म का नाम लेकर एक-दूसरे के खिलाफ अपराध और अत्याचार का पहाड़ तोड़ दिया जाता है तब भी धर्म चुप रह जाता है। जाहिर है, धर्म हमारे जीवन में व्यावहारिक बदलाव लाने से चूक रहा है, क्योंकि हम धर्म या मजहब की वास्तविक आत्मा से दूर हो गए हैं।

सरकारें, राजनीतिक दल और समाज के छोटे-छोटे समूह तो अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहेंगे, लेकिन धर्म में सम्मान पाने वाले लोग अगर इस संबंध में लोगों को महिलाओं का सम्मान करने की सख्त हिदायत दें, तो यह समाज की बड़ी सेवा होगी। मगर कभी-कभी विचार आता है कि क्या धर्म इस संबंध में कुछ कर पाएगा? जरूरत है कि महिला सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार समाज को जागरूक किया जाए। एक बार समाज में सुधार आ गया तो पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है, क्योंकि यह मामला पूरी तरह समाज से जुड़ा है और इसमें राजनीति की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है।

(साभार : जनसत्ता)

पाठकों से अपील

'वॉयस ऑफ बुद्धा' के सभी पाठकों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक वार्षिक शुल्क/शुल्क जमा नहीं किया है, वे शीघ्र ही बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के नाम से टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 को भेजें। शुल्क 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के खाता संख्या 0636000102165381 जो पंजाब नेशनल बैंक की जनपथ ब्रांच में है, सीधे जमा किया जा सकता है। जमा कराने के तुरंत बाद इसकी सूचना ईमेल, दूरभाष या पत्र द्वारा दें। कृपया 'वॉयस ऑफ बुद्धा' के नाम ड्राफ्ट या पैसा न भेजें और मनीआर्डर द्वारा भी शुल्क न भेजें। जिन लोगों के पास 'वॉयस ऑफ बुद्धा' नहीं पहुंच रहा है, वे सदस्यता संख्या सहित लिखें और संबंधित डाकघर से भी सम्पर्क करें। आर्थिक स्थिति दयनीय है, अतः इस आंदोलन को सहयोग देने के लिए खुलकर दान या चंदा दें।

सहयोग राशि:

पांच वर्ष : 600 रुपए

एक वर्ष : 150 रुपए

डॉ. उदित राज ने नांगलोई का दौरा कर वर्षों से रुके परियोजनाओं को शुरू किया

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2014 : डॉ. उदित राज आज बीएसईएस, एनडीपीएल, दिल्ली जल बोर्ड एवं एमसीडी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सुल्तानपुरी रोड, नांगलोई का दौरा कर कई वर्षों से रुके परियोजनाओं का जायजा लिया एवं त्वरित कार्रवाई की। ओपन सत्र के दौरान स्थानीय निवासियों और दुकानदारों सहित सैकड़ों लोगों के बीच डॉ. उदित राज ने विभिन्न विभागों से संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को उनसे संबंधी रुके कार्यों को जल्द पूरे करने के आदेश दिए। इसके अनुसार, नांगलोई के सीवर लाईन अगले 10 दिनों में तैयार हो जाएगा, जनता मार्केट में पंपिंग के कार्य अगले तीन दिनों में शुरू हो जाएगा साथ ही बाजार में खंभों को दो दिनों में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ध्यान देने योग्य बात है कि ये सारे कार्य कई वर्षों से लंबित होने के कारण यहां के निवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। यहां के लोगों को इन परेशानियों से अब जल्द निजात मिलने जा रही है।

इस मौके पर डॉ. राज ने लोगों को विश्वास दिलाया कि भाजपा जनता को अधिक से अधिक शासन उपलब्ध कराने के अपने वादे पर खरी उतरेगी और हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि सभी आवंटित परियोजनाओं को ठीक तरीके से लागू कराया जाए।

अंत में केजरीवाल पर प्रहार करते हुए उदित राज ने कहा कि "केजरीवाल आयकर विभाग में मेरे जूनियर थे और उन्होंने विभाग की बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया। केजरीवाल प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद कर रहे थे और इसलिए मुख्यमंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया लेकिन आज स्थिति यह हो गयी है कि उनके लिए विधायक की सीट भी अब जीतना मुश्किल होगा।"

इस कार्यक्रम के अवसर पर प्रदीप बाबु (चीफ इंजीनियर, एमसीडी), रणवीर सिंह (अतिरिक्त उपायुक्त), एस. एल. मीणा, रमेश ठाकुर (दिल्ली जल बोर्ड), एम. पी. गुप्ता (एमडी, एनडीएमसी, एसई परियोजना) और अनिल शर्मा (एजीएम, टाटा पावर, एनडीपीएल) उपस्थित थे। इस कार्यक्रम को आयोजित करने में स्थानीय भाजपा नेता नरेंद्र बिंदल और श्री. विनोद कटारिया की अहम भूमिका रही।

अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ
All India Confederation of SC/ST Organisations

Dr. Udit Raj
National Chairman

Corres.: T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001
Tel: 011-23354841, 011-23354842, Fax: 011-23354843
Email: dr.uditraj@gmail.com, web.: www.uditraj.com

Circular No. : 80 Dated 26th July, 2014

Dear

Most of the members of the Confederation know about the circumstances in which I decided to enter into Parliamentary Politics. I have been elected to the parliament from North West Delhi. My personal interest or satisfaction comes way later, the primary guiding force, for me ? Is the empowerment of Dalits, Adivasis and the backward classes. I had stressed on this goal while joining the BJP also and I shall be determined towards this goal throughout my life. However, my entrance into the parliament shall bear fruits only if the confederation works even harder for the cause that we have set as our life goal. BJP alone has 282 seats in the parliament but Reservation or Dalit empowerment did not become an electoral issue. No party made Dalit empowerment as the centrepiece of its campaign. If one can gain power without raising the issue of Dalit empowerment, to what extent can I alone rake up the issue of Dalit empowerment and especially if it is not complemented by social movements. This time my friends of the movement have fully supported BJP and for that I believe they should be given all the credits. My main condition to join BJP was the inclusion of Dalits in all the sectors and if Dalits are given their due share in all the sectors they would continually support the BJP.

Confederation alone has been fighting the struggle for protection of reservations for last 17 years but it has not received the expected support. Criticising Brahmanism alone is misunderstood as the struggle but this is not right . We must adopt a positive approach and must try to include ourselves into the various sectors by collaborating with those who own and control resources in the country. If we energise our social movement , our inclusion in the various sectors will automatically increase.

The impact of my entering into the parliament has already started showing results. Before this session, never has the discussion on budget also included discussion on the Social Justice and Empowerment. Discussion on the ministry of Social Justice and empowerment was kept for the last but by the time its turn would have come session would have already ended . So, I met Speaker of the Lok Sabha, Shrimati Sumitra Mahajan, Parliamentary affairs minister Shri Venkhaiah Naidu, Minister for Social Justice and Empowerment Shri Thawar Chand Gehlot and Chief Whip Shri Arjun Meghwal and asked them how would the society react if the ministry that deals with more than 25% of population does not get discussed in the parliament, How will I be able to answer them? You would be pleased to know that for the first time, a discussion on the ministry of social Justice and empowerment was conducted as part of the discussions on Budget and I was chosen as the first speaker from the side of BJP to speak on this issue. Post independence what all has been done against us was discussed for the first time in the Parliament.

It is about time now that we re-energise the struggle for the protection of our rights and for this purpose, National Seminar will be held on the 16th and 17th of August,2014 at 10 am at Speaker Hall, Constitution Club, behind RBI near Patel Chowk Metro Station, New Delhi-110001.

This program is being organized under the patronage of Shri Vinod Kumar, National General Secretary, Shri Netram Thagela, National General Secretary and Dr. Nahar Singh, President, Delhi Pradesh. Do give prior information of your participation in the program. You could contact Shri Vinod Kumar at the following number – 09871237186 or email at vinodkumarijp@gmail.com.

With Regards,

Yours

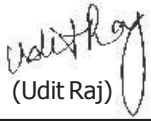

(Udit Raj)

शेष पृष्ठ 1 का ...

सामाजिक न्याय मंत्रालय पर डॉ. उदित राज का संसद में भाषण

empowered like SC, ST Commissions. I would request the hon. Minister of Social Justice to do that. I would suggest one thing. यह पैसा कम है, लेकिन जब यह पैसा भी जाता है तो यह मिसयूटीलाइज होता है, डायवर्ट होता है और जब रोड बना दी जाती है तो यह कहा जाता है कि 16-18 प्रतिशत दलित भी इसको इस्तेमाल करते हैं। That is not meant as Special Component Plan. लगभग पौने छः करोड़ का प्लान बजट है और 12 करोड़ रुपये का नॉन प्लान बजट है। नॉन प्लान बजट बढ़ता जा रहा है और प्लान बजट में जो प्रतिशत दिया जा रहा है, It is not adequate. इसे 95 करोड़ रुपये होना चाहिए था, जो कि आज 50 हजार करोड़ रुपये है। यह हमारी सरकार की कोई गलती नहीं है। अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि यूपीए की सरकार ने यह किया था, वह किया था, हमारी सरकार उसको ठीक करेगी। मोदी जी ने कहा था, My destiny is to do what could not be done. हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2 मार्च को लखनऊ में कहा था कि आने वाला दशक दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का है। मैं समझता हूं कि ऐसा होगा। लेकिन हमारे सामने बैठे मेरे साथियों ने 55 साल तक इस देश में राज किया है, आज तक हमें इस काबिल नहीं बनाया है कि बिना रिजर्वेशन इस संसद में हम घुस सकें, विधान सभा में घुस सके। यह आपने हमें दिया है। पिछले दस साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। इसके पहले वाजपेयी जी की सरकार में तीन संविधान संशोधन हुए थे। ... (व्यवधान)

(इति)

HOW A CORRUPT JUDGE CONTINUED IN MADRAS HIGH COURT

Justice Markandey Katju

This expose is by Justice Markandey Katju, who was chief justice of Madras high court before becoming a Supreme Court judge. He is now chairman of the Press Council of India.

There was an additional judge of the Madras high court against whom there were several allegations of corruption. He had been directly appointed as a district judge in Tamilnadu, and during his career as district judge there were as many as eight adverse entries against him recorded by various portfolio judges of the Madras high court. But one acting chief justice of Madras high court by a single stroke of his pen deleted all those adverse entries, and consequently he became an additional judge of the high court, and he was in that post when I came as chief justice of Madras high court in November 2004.

That judge had the solid support of a very important political leader of Tamil Nadu. I was told that this was because while a district judge he had granted bail to that political leader.

Since I was getting many reports about his corruption, I requested the Chief Justice of India, Justice RC Lahoti, to get a secret IB inquiry made about him. A few weeks thereafter, while I was in Chennai, I received a call from the secretary of the CJI saying that Justice Lahoti wanted to talk to me. The CJI then came on the line and said that what I had complained about had been found true. Evidently the IB had found enough material about the judge's corruption.

Since the two-year term as additional judge of that person was coming to an end, I assumed he would be discontinued as a judge of the high court in view of the IB report. However, what actually happened was that he got another one year's appointment as an additional judge, though six other additional judges who had been appointed with him were confirmed and made permanent judges of the high court.

I later learned how this happened.The supreme court collegium consists of five most senior judges for recommending names for appointment as a supreme court judge, and three most senior judges for dealing with high courts.

The three most senior judges in the supreme court at that time were the chief justice of India, Justice Lahoti, Justice YK Sabharwal, and Justice Ruma Pal. This supreme court collegium recommended that in view of the adverse IB report the judge should be discontinued as a high court judge after his two-year term was over, and this recommendation was sent to the central government.

The UPA government was at the centre at that time. Congress was no doubt the largest party in this alliance, but it did not have a majority in Lok Sabha, and was dependent on the support of its allies. One such ally was the party in Tamilnadu which was backing this corrupt judge. On coming to know of the recommendation of the three-judge supreme court collegium they strongly objected to it.

The information I got was that Prime Minister Manmohan Singh was at that time leaving for New York to attend the UN general assembly session. At the Delhi airport, he was told by ministers of the Tamilnadu party that by the time he returned from New York his government would have fallen as their party would withdraw support to the UPA (for not continuing that additional judge).

On hearing this, Singh panicked, but he was told by a senior Congress minister not to worry, and that he would manage everything. That minister then went to Justice Lahoti and told him there would be a crisis if that additional judge was discontinued. On hearing this, Justice Lahoti sent a letter to the government of India to give another term of one year as additional judge to that corrupt judge, (I wonder whether he consulted his two Supreme Court collegium members), and it was in these circumstances this corrupt judge was given another one-year term as additional judge (while his six batch mates as additional judges were confirmed as permanent Judges).

The additional judge was later given another term as additional judge by the new CJI Justice Sabharwal, and then confirmed as a permanent judge by the next CJI Justice KG Balakrishnan, but transferred to another high court.

I have related all this to show how the system actually works, whatever it is in theory. In fact, in view of the adverse IB report the judge should not even have been allowed to continue as additional judge.

(Courtesy : Times of India)

Rest of Page-8...

The reason for attraction towards Civil Services

that Civil services does not only provide with good wealth but also power. In the villages of UP and Bihar, the Police Inspector of the police station is respected more than the Professor. Even if these candidates would be given the chance to earn thrice as more than the money given in the bureaucracy in the private sector , they shall still opt for Bureaucracy. As part of the preparation for Civil Exams, candidates are taught to give a standard answer that their reason to enter into Bureaucracy is Social service and serving the nation. This certainly is a half truth, bringing forth the real truth will result into a controversry and therefore I shall avoid going further but indeed you know what I am hinting towards.

The students who major in the Indian languages are protesting today and while there demand is genuine but it lacks the holistic approach to analyzing the overall situation. Their case is that translation in Hindi inhibits their chances to get through the exams and CSAT too favours the students with the English background. This however does not bring forth the actual case. After 1990, Privatization expanded in the country, Education sector too came under its grip . Today, more than 60% of higher education has come directly under the Private forces. Primary education is anyway under the grips of privatization. Private institutions not only have better teachers but also have better facilities and the education in government schools is almost minimal. This also is a worthwhile fact that most of the studious children tend towards Science and Mathematics and as a result even if their medium was not English in the beginning but gradually it becomes English. This too is a reason why candidates who have a background in Indian languages are increasingly failing to make the cut. The new educational system wherein students are promoted till class tenth without having to appear for real examinations is majorly harming the students with the background in Indian languages. This system must be immediately ended. Due to privatization of education and freedom from examination , Students who have a background in Indian languages are at a major disadvantage. CSAT, Translation based problems, English language are a hurdle anyway. At this point of time, the country faces a major challenge in solving this problem. If one removes English then also there is a problem. Majority of work that the Indian Government executes, it executes in the English language. One cannot sustain without English in High Courts and Supreme Court. If a South Indian Civil servant serves in UP or a civil servant from North India serves in South India, then without English how will they converse? Decision making, numerical skills, reading comprehensions etc. has caused these candidates to fall short of performing well in these exams. However, if these skills are removed then the talent that is required for the job will be lost out. A Bureaucrat on an average must be equipped with the minimum skills of mathematics, decision making, analysis etc. Today, this is the real challenge and what the country requires is that it finds a way to strike the right balance so that the talent that we ideally require for a Civil Servant is also preserved and at the same time, candidates from the Indian language background are also not harmed.

Rest of Page-8...

Dr. Udit Raj's Speech in Lok Sabha on the Ministry of Social Justice

state governments. I would also like to say something regarding the OBC commission as well. OBC commission is toothless. OBC commission has to be empowered like SC/ST commissions. I would request the Hon. Minister of Social Justice to do that. I would suggest one thing. This amount is less and also the money is misused, diverted and when a road is made then it is said that even 16-18% Dalits also use it. That is not meant as special Component Plan. Almost 5.75 Crores is for the plan Budget and 12 crores for the non-plan budget. Non- plan budget is increasing and the percentage for plan budget, It is not adequate. It should have been 95 crores which is 50,000 crores today. This is not the fault of our government. Just now our Hon'ble member was saying that UPA government did this and did that. Modiji has said that, "My destiny is to do what could not be done". Our Prime Minister had said in Lucknow on 2nd March that the coming decade shall belong to Dalits, Backwards and Adivasis. I think this shall happen but our colleagues sitting infront of us have been ruling for the last 55 years and till now they could not empower us to the extent that we could enter the parliament without reservations, enter state assemblies without reservations. The UPA Government has done nothing in the last 10 years. Before this Vajpayee government executed three constitutional amendments.

....Interruptions...

Dr. Udit Raj's Budget Speech in Lok Sabha on 17th July, 2014

DR. UDIT RAJ (NORTH WEST DELHI): Thank you.

I rise to express my observations and feelings on the Budget. I have gone through the Budget a couple of times. I found that this Budget is not of any particular section or community only but I would say that this Budget is of the nation.

I must congratulate the hon. Finance Minister that he had deep insight and understanding about society. So, this Budget addresses the problem of water, electricity, housing, and social justice, ranging from poor to rich.

1307 hours (Dr. M. Thambidurai in the Chair)

Hon. Member Shri Mulayam Singh Yadav was asking what was there in the Budget for the farmers. I would say, if you go and read the previous Budget and also this Budget, you would find that this Budget has focused enough on farmers.

One more remarkable achievement of the hon. Finance Minister I have found in the Budget is that earlier the fiscal deficit was 4.7 percent, now he has kept it at 4.1 percent. Fiscal consolidation is a must. He has tried in a short span of time to control fiscal deficit. Looking at the Budget, I am sure, he would be in a position to control the fiscal deficit.

I would suggest some measures to the hon. Finance Minister on how to control fiscal deficit. I would suggest that the tax base has to be expanded; not only that but non-tax revenue also has to be enhanced and borrowings minimised. So far, there has been a large amount of borrowing and the Government has been paying a huge amount of interest. That is also causing fiscal deficit.

Your Budget is encouraging for the investors and even for the domestic business persons. They are now seeing that the fiscal deficit is coming down. Of course, what you have envisaged is to keep or achieve a low fiscal deficit in the years to come.

(c2/1310/vp/jr)

In the coming years, he will bring it down to 3.6 percent and then, to three percent – in 2016, it will be 3.6 percent and in 2017, it will be three percent. I have observed the mood of the business and the share market; they are very much enthused by this step. However, he has got something inherited. A lot of things have been given to you as part of the inheritance. Even then he has tried his level best to reduce it. Income tax refund to the tune of Rs. 50,000 Crores was not issued before March because of which a liability of Rs. 50,000 Crores was created. Our Government is going to face this. With regards to the Goods and Services taxes a meeting was held in 2010 and these taxes were promised as compensation to states, this amount turns out to be Rs. 32,000 Crores. This amount also has been left over by the past government. As a result, a total amount of Rs. 82,000 Crores turns out to be a liability that has to be compensated by our Government.

Everybody knows that increasing the railway fare was proposed already. I was reading the Times Of India in the morning and the first thing that struck my mind was "Mallya's Kingfisher Airlines is King of defaulters". Kingfisher Airlines has an NPA of Rs. 4022 crores which the Government has to pay. In the similar way, Winson Diamonds has 3,243 Crores, Electrotherm India has 2,653 crores, Corporate Power has 2,487 Crores, Sterling Bitech has 2,031 Crores. Revenue Pressure has an NPA of 1,754 Crores. All this has to be paid by the government. This is the legacy of the past government. They took the loans for thousands of Crores and then declared themselves as bankrupt. They declared themselves bankrupt and siphoned off money in the name of their off-springs and progenies; they are having great lives not only in this country but also outside. The past government has never been serious about the NPA and the result of this is that today the amount of money attached with the NPA has escalated upto 5 to 6 lakh Crores. If we can recover this money then we would not have to worry about the subsidies. My demand as well as suggestion is that subsidies allocated for the farmers must not be decreased. Apart from this I have also seen that Income Tax Department finds Rs. 1 Lakh Crores in the undisclosed income in one year. 1 lakh Crore as the tax evaded income has been found in one year as part of the search and seizure process . I think that managing the Budget Deficit is not a very difficult task. I am very hopeful that the very able and ofcourse wise Finance minister is going to do it.

I would also like to request that expenditure size should not be cut, one could however certainly manage the expenditure but it should not be cut. We should give emphasis on revenue collection. The budget also addresses the growth. It says that we will avail growth at the rate of 7-8% in the future. We will have growth in every sector. Enough provisions have been made in this budget so that there is growth in several sectors like agriculture, skill development, etc. Saving is also going to be increased because there is increase in ceiling under 80 C and home loan. Hon'ble Finance Minister's step to allocate 37,000 Crores for infrastructure development will promote growth.

Our Honourable Prime Minister has given extra ordinary emphasis on Governance and that is why we shall move towards all round growth. I am very grateful to you and thank you on behalf of all the members of Parliament from Delhi for having spared Rs. 500 crores for drinking water. The biggest problem of the banks has been sorted out something that has not been addressed since independence, relaxation of SLR and CRR on pre-condition basis will allow for long term investment in the infrastructure and will allow the banks to maintain capital and also not allow for mismatches. Mr. Chairman, Sir, I am going very fast because of the time constraints. Otherwise, I would have elaborated all these points. With regards to Agriculture, under Pradanmantri Krishi Sinchai Yojana, 1000 Crores has been allocated. Shri Mulyam Singh Yadav was just now asking, what has been done for the farmers, so let me tell him that it is for the first time that 1000 Crores have been aloted under Pradanmantri Krishi Sinchai Yojana. If the National market is established, the farmers would be able to sell their products anywhere in the country. The exploitation that the farmers had to otherwise undergo will be stopped and they will no longer suffer. I would like to thank you for having spared Rs. 2,000 Crores for NABARD towards Producer's Organization Development Fund to build 2000 Producers organizations in India.The amount of Rs. 2,000 Crores that has been kept for the establishment of the farmer's organizations will bring about a massive change in the lives of the farmers. I am very sure about it. 5,000 Crores that have been kept aside for the development of warehouses shall be put to use by solving farmer's woos with the perishable items. He is going to get a big relief. I thank you for this also. Another important point is about the tax revenue. I am not going into the details of the plan and the non- plan budget but I would like to say that we need to enhance the revenue. That is not being done here. The Finance Minister has taken a number of measures. A high level Committee consisting of CBDT and CBEC will be constituted to clarify any doubts about the taxation and litigation. That will help the Businessmen a lot. They can consult them and avoid getting into litigation.

You have said that the Settlement Commission will be enlarged. I do agree with you. This is a practical step. One request that I would like to make to you is that the Settlement Commission should be made accountable.

Hon. Chairperson (Dr M. Thambidurai): Please Wind up. You have taken 15 minutes.

Dr. Udit Raj(North West Delhi) : I know a case where the assessing officer fixed the tax liability of about Rs. 1000 Crores but the settlement commission settled it for less than Rs. 25 Crores. So, there should be some accountability fixed on the part of the settlement Commission. You have done a lot for the tax disputes of four Lakh that are right now in the process of litigation. I want to say one more thing there is a lot of hue and cry about the taxes. Kindly let me read. Australia has an individual tax rate of 50%

Hon. Chairperson (Dr M. Thambidurai): Please Wind Up.

Dr. Udit Raj(North West Delhi): France has a 45% tax rate, Japan has 50%

Hon. Chairperson (Dr M. Thambidurai): You have taken 15 minutes

Dr. Udit Raj(North West Delhi): Netherland has 52% , Sweden has 57%

Hon. Chairperson (Dr M. Thambidurai): Please Sit down.

...Interruptions...

Appeal to the Readers

You will be happy to know that the **Voice of Buddha** will now be published both in Hindi and English so that readers who cannot read in Hindi can make use of the English edition. I appeal to the readers to send their contribution through Bank draft in favour of **'Justice Publications'** at T-22**,** Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001. The contribution amount can also be transferred in 'Justice Publications' Punjab National Bank account no. 0636000102165381 branch Janpath, New Delhi, under intimation to us by email or telephone or by letter. Sometimes, it might happen that you don't receive the Voice of Buddha. In that case kindly write to us and also check up with the post office. As we are facing financial crisis to run it, you all are requested to send the contribution regularly.

Contribution:
Five years : Rs. 600/-
One year : Rs. 150/-

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 17 ● Issue 17 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● 16 to 31 July, 2014

Dr. Udit Raj's Speech in Lok Sabha on the Ministry of Social Justice

While passing the Budget in the Parliament, approval of allocations for different Ministries is taken. On 23rd July, 2014, approval of allocations for different Ministries was to be taken after discussions. First of all, discussion was to take place on road transportation and in the end, discussion was to take place on the allocations of the Ministry of Social Justice and Empowerment. Dr. Udit Raj met the Honorable Speaker and said that the Ministry of Social Justice and Empowerment is not only deeply concerned with the 25% population of Dalits and Adivasis but is also concerned with the welfare schemes of the OBCs. It is irony that without any discussions or deliberations, the allocations of this Ministry were approved. Dr. Udit Raj brought this fact to the notice of the Parliamentary Affairs Minister. The Minister of Social Justice, Shri Thawar Chand Gehlot and BJP Whip Shri Arjun were also made aware of this situation and they were quite cooperative. For the first time in the history of the parliament, there was a discussion on the demands of this Ministry and certain fundamental issues were raised which was not done in the past.

Dr. Udit Raj (North West Delhi) : Hon. Chairperson, our Hon. Finance Minister has just presented the Budget. The allocation made by him in the Budget for SCs in the scheduled castes plan Budget is Rs. 50,548 crore and for scheduled tribes, the allocation is Rs. 32,387 crore.This works out to be 8.79 % where as it should be around 16%. Through you, I would like to bring to the notice of Hon. Minister that it should be around 16% and for the Scheduled tribes it should be 7.5 %. I shall come to this point later but what is most important is that a flaw has been committed by the officers and that is if you see page number 316 one would realise that 50,000 crores which is going to be spent for SC/STs, now it seems that it is going to be spent by the Central Government. It is going to be spent by the states and UTs. I would like to present through you two or three important figures. Post metric scholarship which in 2012-2013 used to be 1654 crores that used to be under the head of Central Government Ministry of Social Justice, this amount has now gone under State and UT plan with an amount of 14999 crores. One is confused whether this amount shall be transferred to the state government, whether the Government will spend it or if the Central Government shall implement this. If this shall be implemented through state government then this has been going on but attempts were made even then that this money be transferred to the state.Hon. Minister I would like to know if this money is being given to the states? We do not have faith in many of the state governments, these state governments are feudal, anti- dalit. In UP, one can see that anti- reservation activities were carried out by the Government itself. How can we have faith in them? We do not have any faith in them and that is why this money should be utilized through Central Government's ministry of Social Justice and empowerment. Similarly, there is a machinery for the implementation of protection of Civil Rights,1955. It was 97 crores before, though on certain occasions the amount has been lowered down. For example, for the girl's hostel in comparison to earlier budget this time the amount is lesser. In the similar way, amount has lowered down for the Post-metric scholarship. I would like to request the Hon. Minister that if a lot can't be increased but in comparison to past years inflation has also risen. One must try to enhance this. Similar things have happened to the OBCs . The budget for OBCs was earlier implemented through the Ministry of Social Justice and empowerment. Similar pattern can be seen here. It is likely that the officers have misled. Of course, we know that the bureaucracy does. I was part of the bureaucracy.

Through you, I would like to request the Hon. Minister that this should be done like the past and the money not be sent to the

Rest on Page-6...

The reason for attraction towards Civil Services

Dr. Udit Raj

This year, out of the candidates who succeeded in the Civil Services, majority belonged to the English background. This resulted in a slew of protests beginning from Mukherjee Nagar and then gradually spreading all over. In 2009, the percentage of candidates belonging to Hindi background who qualified civil services was 25.4 %, in 2010 the number dropped to 13.9% and finally went down to 2.3% in 2013 and as such, the participation of Hindi belt in the shaping up of India's Bureaucratic circles has reduced and every year the number seems to be continually dropping.

I too gave the Civil Services examinations in 1988 and was selected for the Indian Revenue Services. In 1990, my first appointment came in the form of Assistant Income tax Commissioner. The push for me to enter into civil services came from my financial background but in 2003, I resigned from the post of Additional Commissioner of Income Tax. Before 1980, students from the science and engineering background mostly did not appear for the Civil Services. Post 1980, the attraction for Bureaucracy was fairly visible amongst the IITians. Because the earlier system of two optionals and one General studies was replaced by two general studies and one optional, Engineers and doctors started to benefit more.

In the initial years of independence, candidates from Kerala dominated the Civil Services with maximum number of successful candidates hailing from the state but gradually, Allahabad became the centre of Civil Services and after that JNU and Delhi University followed. Because of globalization, one felt that most talented would opt for jobs in the private sector due to the higher wages and better facilities . For some time this did happen but the attraction towards Civil services did not wither down. The attraction for Civils is higher in the states that have witnessed minimal development. Where there is no opportunity to excel in fields like Trade, Commerce, art and culture, Tourism etc., the urge to get through Civil Services is fairly obvious. For example in Bihar, there are minimal opportunities in the business sector or any other such sector which could provide comfortable

livelihood. As a result there is a huge attraction for Civil Services in Bihar. In states like Andhra Pradesh, Kerala, Tamil Nadu etc. corporate culture has developed and therefore Civil Services alone is not the only option there. So while in the beginning, these states dominated the Civil services exams, today that is not the case.

It is important to analyze the reason behind the massive urge amongst students to enter into Bureaucracy. It has been generally observed that people with a traditional and feudal outlook tend to be attracted more towards Civils. The reason for this is

Rest on Page-6...

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.
Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com Computer typesetting by N. K. Karn